शारदा नहर परियोजना

4687. श्री जैनुल बशर : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में शारदा सिंचाई परियोजना के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले इसके अंतर्गत आएंगे और उपरोक्त नहर से कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी ; और

(ग) उपरोक्त नहर परियोजना पर कार्य की प्रगति के बारे में क्या ब्यौरा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समूचे राज्य को दी जाती है और यह विकास के किसी सैक्टर अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है। तथापि, इस परियोजना की वित्तीय स्थिति, जिसका वित्त-पोषण उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, निम्न प्रकार :—

	करोड़ रुपए में
अनुमानित लागत (अद्यतन)	426.00
1981–82 तक हुआ व्यय	352.73
बजट आबंटन 1982–83	23.75
1982–83 (दिसम्बर, 82 तक) में वास्तविक व्यय	14.80
1983-84 के लिए प्रस्तावित परिव्यय	20.00

(ख) शारदा सहायक परियोजना से राज्य के 14 जिलों अर्थात् लखीमपुर, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जौनपुर, आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में 20 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र कमान के अन्तर्गत आ जाएगा। प्रारम्भ में 96—की सिंचाई गहनता के साथ, 19.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई करने का प्रस्ताव है, जिसमें पुराने क्षेत्रों में सिंचाई का द्रढ़ीकरण भी सम्मिलित है।

(ग) घाघरा नदी पर गिरिजा बराज और शारदा नदी पर बराज तथा अन्तर्योजक जलमार्ग और साथ ही पोषक नहर, जो इन नदियों के संयुक्त उपलब्ध जल का वहन करेंगी, पर कार्य पूरा हो गया है। वितरण नहर प्रणाली पर 88% मिट्टी का कार्य और 59% चिनाई कार्य, जिसमें पुनरूपण का कार्य सम्मिलित है, पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। जून, 1983 तक 15.60 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन कर लिए जाने की प्रत्याशा है।

मंत्रालय/विभागों द्वारा वर्ष 1982 के दौरान की गई विभागीय परीक्षाएं

4688. श्री रामावतार शास्त्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान उनके मंत्रालय/विभाग और उनसे सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा कितनी विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई हैं ;

(ख) क्या उन विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प दिया गया था और यदि हां, तो ऐसी परीक्षाओं की संख्या कितनी हैं,

(ग) सभी विभागीय परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को हिन्दी माध्यम परीक्षा देने की अनुमति कब से दी जाएगी, और

(घ) इस संबंध में समुचित व्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (इन्द्र अकदाना) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

(ग) गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों में "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में चुनने की पहले से ही व्यवस्था है । गैर हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विभागीय अभ्यार्थी भी इसे चुन सकते हैं ।

(घ) इस उद्देश्य के लिए जरूरी व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है ।

ग्रामी आवास के लिए मध्य प्रदेश को राशि का आबंटन

4689. श्री मार्तण्ड सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को ग्रामीण आवास योजना के लिए वर्ष 1982--83और 1983--84के लिए सरकार द्वारा आबंटित की गई धनराशी का ब्यौरा क्या है और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) :

(क) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों को आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना जो न्यूननम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है के अन्तर्गत मध्य प्रदेश 1982--83 के लिए स्वीकृति परिव्यय 346 लाख रुपए और 1983-84 के लिए 450 लाख रुपऐं है ।

(ख) अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक की अवधि के लिए बतलाई गई उपलब्धि 20,898 आवास स्थल तथा 19,149 परिवारों को निर्माण सहायता है ।

Maharashtra's Scheme to increase Groundnut Production

4690. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Maharashtra had formulated a special scheme for increasing groundnut production in the State and referred it to Centre;

(b) if so, what are the details of this scheme aid to what extent the present productlion can be raised;

(c) whether the State Govermment had pleaded that because of their financial difficulties, the scheme should be financed fully by the Centre, as they had done in the case of Gujarat;

(d) if so, when this Scheme was received by the Central Government and what decision, if any, taken in this regard; and

(e) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN). (a) Yes, Sir.

(b) The scheme, *inter alia*, envisaged raising production of groundnut to 10.89 lakh tonnes by 1984-85 through the use of certified/truthfully labelled seed of improved varieties, seed treatment, extension of area under protective irrigation, use of fertilizers, adoption of plant protection measures, expansion of area under inter-cropping, maintenance of adequate population, extension of area under summer groundnut and adoption of water harvesting technology.

(c) Yes, Sir.